

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
11/7/19	<p>यह अपील 12.7.19 को अपीलार्थी द्वारा 24.5.2017 के उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के शास्ता स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध निर्णय को अपास्त करने एवम् साथ ही एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है.</p> <p>(i) प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ दफा 5 मियाद आचिनियम एवम् धारा 96 सि० प्र० सि० प्रस्तुत किये - अपील मियाद शुमार तथा मामले में प्रभावित पराकार होने से सुनने का अधिकार होने की पैरवी की.</p> <p>(ii) आगे कहा कि चक्र. 11 BGD के प.न. 171/395 मु.नं० 38 के किला नं. 1.10, 11, में 20x495 फुट का शास्ता स्वीकृत करने का आदेश 24.5.17 को किया गया जिसकी जानकारी उसे नहीं हो सकी.</p>	

10/7/19

(iii) अपीलार्थ का अर्थ है कि उसके द्वारा उम्ह भूमि 16.7.2008 को ^{1/8 हिस्सा} खरीद ली गई थी - किन्तु उसका नामांतरण ^{उम्ह} निर्णय होने तक नहीं हुआ था

यह आवश्यक पदाकार था किन्तु इसे पदाकार नहीं बनाया

(iv) चूंकि अब उसका नामांतरण करण हो चुका - इसलिये यह अपील 2 वर्ष की देरी से मिथाद मे दूर के प्रां पत्र व ^{धारा} 96 CPC. के प्रां पत्र के साथ प्रस्तुत की है

(v) हमने प्राथी के विद्वान अधिकृत की बहस व तर्क सुने, प्रां पत्र व निर्णय का अवलोकन किया

(vi) प्राथी ने यह अपील 24.5.2017 के उपखण्डाधिकारी रायसिंहनगर के आदेश के विरुद्ध 12.7.2019 को लगभग 2 वर्ष 2 माह पश्चात अनापदध्युत विलंब व बिना किसी ठोस कारण व औचित्य के प्रस्तुत की है

—लगातार—

(b) अपीलार्थी मूल वाद में पक्षकार नहीं था जो ही तत्समय वह शहरे के विवाद में सुनवाई का हक रखता था. क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि तत्समय रजिस्ट्रार के नाम में भूमि में उसका नाम दर्ज नहीं था.

(c) उसका कथन कि उसने उम्ह शहरे के विवाद के निर्णय वाली भूमि का 1/8 हिस्सा 16.7.2008 को खरीद लिया था व कब्जा ले लिया था - तो यह कैसे यह सफल है कि उसे विवाद का पता नहीं?

(d) वास्तव में उसके विषय विलेख का दायित्व रूप से नामांतरण करण इस निर्णय 24.5.17 के पश्चात हुआ जैसा कि प्रार्थी ने प्रकृत पर कहा.

- इसका तात्पर्य यह है कि निर्णय के समय जमाबन्दी में उसका नामांतरण नहीं हुआ इसलिये वह पक्षकार नहीं हो सकता था. ना ही तत्समय वह हिलबट्ट था - फलतः यह निर्णय हिलबट्ट पक्षकारों के बीच हुआ. अतः प्रार्थी निर्णय से प्रभावित नहीं हुआ.

(e) निर्णय के 2 वर्ष 2 माह पश्चात् अपील करने का औचित्य नहीं है.

फलस्वरूप - उम्ह विवेचन से प्रार्थी की अपील अतिरिक्त बाहर मामले में निर्णय से प्रभावित व हिलबट्ट नहीं होने से - अपील एडमिशन स्तर ही सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य पाई जाती है - निर्णय हो पश्चात् से कम हो

डॉ. रजेश कुमार शर्मा
RAA.